

e-ISSN: 2583 – 0430

कृषि-प्रवाहिका: ई-समाचार पत्रिका, (2025) वर्ष 5, अंक 3, 10-13

Article ID: 504

फल प्रसंस्करण से किसान की आय दोगुनी: मूल्य-संवर्धन के नए अवसर



शिव कुमार अहिरवार

पीएच.डी. शोधार्थी, फल विज्ञान विभाग कृषि महाविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, मध्य प्रदेश – 482004 भारत में कृषि आज भी लाखों किसानों के जीविका स्रोत का मूल आधार है। लेकिन सिर्फ फसल उगाना ही पर्याप्त नहीं — यदि किसान अपनी उपज को केवल मूल रूप में बेचें, तो अक्सर उन्हें उचित लाभ नहीं मिल पाता। यही कारण है कि आज "मूल्य-संवर्धन" या वैल्यू एडिशन (Value Addition) की अहमियत बढ़ गई है। विशेष रूप से फल-फूल (हॉर्टिकल्चर) में, इस प्रसंस्करण (processing) द्वारा किसानों की आय दोगुनी (या उससे भी अधिक) हो सकती है। इस लेख में हम देखेंगे कि कैसे फल प्रसंस्करण से आय बढ़ सकती है, किन नए अवसरों का लाभ उठाया जा सकता है, किन चुनौतियों को पार करना होगा तथा राज्य/केंद्र की कौन-सी योजनाएँ इसमें मददगार हैं।

फल-उत्पादन का वर्तमान परिदृश्य

भारत में फल-फूल तथा सब्जियाँ, कृषि विविधीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण श्रेणी बनी हुई हैं। फलों की पैदावार बढ़ी है, और उपभोक्ता मांग भी बदल रही है (स्वाद, सुविधा, पैकेजिंग आदि में)। इससे किसानों के सामने नए

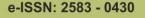
अवसर खुले हैं। दूसरी ओर, प्रसंस्करण का स्तर अपेक्षाकृत कम है — फल/फूल कार्यान्वयन, पोस्ट-हर्वेस्ट लॉस, सही भंडारण एवं मार्केटिंग की कमी के कारण किसान को अपेक्षित मूल्य नहीं मिल पाता। उदाहरण के लिए, भारत का खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र 2019-20 में लगभग ₹2.97 लाख करोड़ की सकल मूल्य संवर्धन (Gross Value Added) हो रही थी, जो 2020-21 में लगभग ₹3.22 लाख करोड़ तक पहुँच गई। इससे स्पष्ट है कि प्रसंस्करण बढ़ रहा है, लेकिन अभी अवसर बहुत हैं।



2. "मूल्य-संवर्धन" क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है?

"मूल्य-संवर्धन" का मतलब है कि किसान अपनी कच्ची उपज (Raw produce) को कुछ ऐसे रूप में बदलें जिससे उसका बाजार मूल्य बढ़ जाए — जैसे कि ताज़ा फल से जूस, मिक्सड फ्रूट पैक, ड्राईड फ्रूट, जाम, जैम, जैली, शुष्क果, पैक्ड स्नैक्स, फ्रोजन फल-सेगमेंट आदि।

यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि:



कृषि-प्रवाहिकाः ई-समाचार पत्रिका

कृषि प्रवाहिक ई-समाचार पत्रि प्रसंस्करण से उपज की

 प्रसंस्करण से उपज की शेल्फ़-लाइफ बढ़ जाती है, बर्बादी कम होती है (पोस्ट-हर्वेस्ट लॉस कम होता है)।

- बाजार में किसान सीधे अधिक मूल्य पा सकते हैं — कच्चे माल बेचने की तुलना में तैयार (processed) उत्पाद की प्रति इकाई कीमत बहुत ज्यादा होती है।
- किसानों को सिर्फ उत्पादन तक सीमित नहीं रहना पड़ता, वे मार्केटिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग में भी भाग ले सकते हैं और बेहतर राजस्व प्राप्त कर सकते हैं।
- प्रसंस्करण से ग्रामीण इलाकों में रोजगार और उद्यमिता बढ़ती है, जो सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से लाभदायक है।
- उपभोक्ता बदल रहे हैं सुविधा-उन्मुख, स्वास्थ्य-सचेत, पैक-फूड की मांग बढ़ रही है। फल-फूल से बने स्वस्थ एवं तैयार उत्पादों की डिमांड बढ़ रही है।

इस प्रकार, फल-प्रसंस्करण किसानों के लिए "आय बढ़ाने" का एक बेहद महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है।

3. प्रसंस्करण से किसान की आय कैसे दोगुनी हो सकती है? नीचे इस प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से समझाते हैं कि कैसे प्रसंस्करण किसान की आमदनी को बढा सकती है:

3.1 उपज की गुणवत्ता व मात्रा बढ़ाना

जब किसान बेहतर किस्म के फल उगाते हैं, समय पर ठीक-ठाक टेक्निक अपनाते हैं तो उपज ज्यादा होती है और/या गुणवत्ता बेहतर होती है। इससे शुरुआत होती है। किन्तु सिर्फ यही पर्याप्त नहीं है — इसके बाद तय-समय पर कटाई, भंडारण, छंटाई, श्रेणीकरण (grading) करना ज़रूरी है, ताकि प्रसंस्करण-योग्य उपज तैयार हो सके।

3.2 पोस्ट-हर्वेस्ट लॉस कम करना

कई बार फल/फूल तुरंत सही तरीके से नहीं कटते, या भंडारण नहीं होता, जिसकी वजह से बर्बादी (Loss) बड़ी होती है। उदाहरण के लिए, पूर्वोत्तर क्षेत्र के एक अध्ययन में बताया गया है कि यदि प्रसंस्करण एवं वैल्यू-चेन ठीक बना दिया जाए तो कृषि उपज में लगभग 10% लॉस कम की जा सकती है।

लॉग लॉस कम होने का मतलब है कि किसान ज्यादा संख्या में बेचे जाने योग्य फल रख सकते हैं — इसका मतलब है अधिक विक्रय-योग्य उपज ⇒ अधिक आय।

3.3 प्रसंस्करण के माध्यम से तैयार उत्पाद बनाना

यह मुख्य चरण है — जैसे कि ताज़ा फल बेचने के बजाय:

- फल को छाँटकर, धोकर, कट-छाँटकर जूस या पल्प बनाना
- ड्राईड फ्रूट (सूखे फल) तैयार करना
- फ्रोजन फल-सेगमेंट बनाना
- फ्रूट कॉम्पोट, जैम, जेली, मिक्सड फ्रूट कैंडी, रेड़ी-टू-ईट पैक बनाना
- पैकिंग व ब्रांडिंग कर बाजार में बेहतर मूल्य पर बेचना

इन तैयार उत्पादों का मूल्य कच्चे फलों की तुलना में बहुत अधिक होता है। शोध में पाया गया है कि छोटे/मध्यम किसान यदि प्रसंस्करण गतिविधियों में शामिल होते हैं तो उनकी आय में 20-30% तक की वृद्धि संभव है।

3.4 बेहतर बाजार पहुँच एवं ब्रांडिंग

जब किसान या किसान समूह अपने प्रसंस्कृत उत्पाद को सीधे उपभोक्ता या खुदरा बाजारों तक पहुँचाते हैं, पैकिंग करें, ब्रांड करें, गुणवत्ता बनाए रखें — तो उन्हें "मध्यस्थों" पर निर्भरता कम होती है। इससे उन्हें बेहतर मार्जिन मिल सकता है। इसके लिए सह-किसान उत्पादक संगठन (FPOs), सहउद्यम, कॉपरेटिव्स बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।

3.5 राज्यों/केन्द्र द्वारा समर्थन एवं योजनाएँ

सरकार ने प्रसंस्करण एवं मूल्य-संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएँ चलाई हैं। उदाहरण के लिए, Pradhan Mantri Kisan SAMPADA Yojana (PMKSY) के तहत प्रसंस्करण इकाइयों, ठंडा-श्रृंखला, कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर्स के लिए अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। ऐसे समर्थन से लागत कम होती है और किसान/उद्यमी प्रारम्भिक निवेश में आसानी पाते हैं।

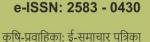
उपरोक्त चरणों के संयोजन से — बेहतर उपज + कम लॉस + तैयार उत्पाद + बेहतर बाजार + सरकारी सहयोग — किसान की आय दोगुनी (या उससे भी अधिक) करना संभव हो जाता है।

4. नए अवसर: फल-प्रसंस्करण में उभरते क्षेत्रों का विश्लेषण

नीचे कुछ ऐसे "नए अवसर" दिए गए हैं जिन्हें विकल्प के रूप में देखा जा सकता है — खासकर यदि आप किसान, किसान समूह, ग्राम उद्यमी हों।

4.1 ऑर्गेनिक व स्वास्थ्य-उन्मुख फल-उत्पाद

आज उपभोक्ता स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं। ऑर्गेनिक फल, बिना





रसायन के उत्पादन, उत्पाद पर पोषण लेबल आदि की मांग बढ़ रही है। ऐसे में यदि किसान जैव-उत्पादन अपनाएँ और प्रसंस्करण करके "स्वास्थ्य-उन्मुख" पैकेजिंग उत्पाद बनाएँ — तो बाजार में अच्छा अवसर है।

4.2 ड्राय/डीहाइड्रेटेड फल, फ्रीज-ड्राई फलों का बाजार

ताज़े फल जल्दी ख़राब हो जाते हैं, लेकिन यदि इन्हें सुखाकर, डीहाइड्रेट करके रखा जाए तो शेल्फ-लाइफ बढ़ जाती है और दूर-दराज के बाजारों में निर्यातकर्ता-मूलक अवसर बनता है। किसानों के लिए यह नए आय-स्रोत का मार्ग हो सकता है।

4.3 फ्रोजन फल और तैयार व्यंजन (Ready-to-Eat/Ready-to-Cook)

उपभोक्ताओं के पास समय कम है, इसलिए फ्रोजन कट फल, मिक्स्ड फ्रूट पैक, तैयार स्मूथी मिक्स आदि की माँग बढ़ रही है। फिर से, अगर किसान समूह मिलकर ऐसे उत्पाद बनाएं तो अच्छा मुनाफा संभव है।

4.4 कृषि-उद्योग संवाद व स्थानीय ब्रांडिंग

छोटे किसान समूह मिलकर एक स्थानीय ब्रांड बना सकते हैं — "हमारा फल", "बनारस फ्रूट्स", "मध्य-प्रदेश ऑर्गेनिक्स" आदि। ब्रांडिंग से उत्पाद को पहचान मिलती है, बेहतर कीमत मिलती है।

इसके अलावा, ई-कॉमर्स व डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर (D2C) मॉडल भी तेजी से बढ़ रहे हैं — किसानों को मध्यस्थों की भूमिका कम करनी होगी।

4.5 निर्यात हेतु अवसर

भारत का फूड-प्रोसेसिंग क्षेत्र निर्यात-क्षेत्र में बहुत संभावनाएँ रखता है। उदाहरण के लिए, फलों-सब्जियों के प्रसंस्कृत उत्पादों का निर्यात बढ़ रहा है। किसानों द्वारा अगर गुणवत्ता, पैकिंग, ब्रांडिंग, निर्यात-लाइसेंसिंग सुनिश्चित हो जाए तो वे अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुँच सकते हैं।

5. चुनौतियाँ एवं समाधान

जब अवसर इतने हों, तब भी किसानों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आइए देखें मुख्य चुनौतियाँ और संभव समाधान।

5.1 चुनौती: निवेश एवं तकनीकी संसाधनों की कमी

फ्रोजन यूनिट, डीहाइड्रेशन मशीन, पैकिंग मशीन, श्रेणीकरण उपकरण आदि की लागत अक्सर किसानों के लिए बड़ी होती है। इसके साथ तकनीकी प्रशिक्षण की कमी भी होती है।

समाधान: केंद्र/राज्य द्वारा दिए जा रहे अनुदान-वित्त (subsidy/credit) का लाभ लें। किसान-उत्पादक संगठन (FPO) मिलकर साझा इकाई स्थापित करें — लागत कम होगी।

5.2 चुनौती: पोस्ट-हर्वेस्ट लॉजिस्टिक्स व ठंडा श्रृंखला (Cold Chain) का अभाव

फल जल्दी खराब हो जाते हैं यदि सही तापमान पर न रखा जाए। समाधान: ठंडा भंडारण (cold storage), प्री-कूलिंग (precooling), बेहतर परिवहन नेटवर्क (कूल ट्रक) आदि आवश्यक हैं। सरकार की योजनाओं के अंतर्गत ये सुविधाएं बढ़ रही हैं।

5.3 चुनौती: मार्केटिंग, ब्रांडिंग व गुणवत्ता मानक (Quality Standards) का अभाव

किसानों को अक्सर सीधे बड़े बाजारों में प्रवेश नहीं होता, पैकिंग/लेबलिंग की जानकारी कम होती है।

समाधान: प्रशिक्षण लें, किसानों-

समूह मिलकर लेबलिंग, ब्रांडिंग व ई-मार्केटिंग सीखें। कोलेबोरेटिव मार्केटिंग प्लेटफॉर्म का निर्माण करें।

5.4 चुनौती: छोटे स्तर पर जोखिम और उपज का अकार्यक्षम उपयोग

छोटे किसानों के लिए अकेले चलने पर जोखिम रहता है — इकाई छोटी होगी, लागत ज्यादा लगेगी। समाधान: किसानों का समूह बनें (एफ़पीओ/FPO), कॉपरेटिव करें, साझा संसाधन बनाएं। इससे जोखिम कम होता है, स्केलिंग संभव होती है।

5.5 चुनौती: स्थिरता एवं पर्यावरण-मित्रता

(Sustainability)

प्रसंस्करण में ऊर्जा-उपयोग, प्लास्टिक पैकिंग, अपशिष्ट (waste) आदि समस्या बन सकते हैं।

समाधान: पर्यावरण-अनुकूल पैकिंग अपनाएं, बायो-प्लास्टिक देखें, अपशिष्ट का पुनःउपयोग करें, सौर ऊर्जा आधारित प्रसंस्करण महसूस करें।

6. राज्य-स्तरीय एवं केन्द्र-स्तरीय पहल

भारत सरकार ने कृषि एवं प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएँ और नीतियाँ शुरू की हैं। मुख्य बातें नीचे दी जा रही हैं:

- प्रधानमंत्री किषान सम्पदा योजना (PMKSY) के अंतर्गत, कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर्स, ठंडा श्रृंखला, पैक-हाउस, ठंडा परिवहन सुविधा आदि पर अनुदान मिलता है।
- खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 'मेक इन इंडिया' पहल भी है। इससे फूड-प्रोसेसिंग सेक्टर में निवेश बढ़ा है।



e-ISSN: 2583 - 0430

कृषि-प्रवाहिका: ई-समाचार पत्रिका

 विस्तृत अध्ययन में यह पाया गया है कि कृषि मूल्य-संवर्धन से ग्रामीण रोजगार बढ़ता है, किसानों की आमदनी सुधरती है।

इन पहलों से किसानों को सहज सहायता मिल रही है — जैसे कि लोन, अनुदान, प्रशिक्षण, समूह गठन, मार्केट लिंक-अप आदि।

7. राज्य (मध्य-प्रदेश) किसानों के लिए सुझाव

आप मध्य-प्रदेश (जबलपुर) के पास हैं — इसलिए कुछ स्थानीय सन्दर्भ में सुझाव देना उपयोगी रहेगा:

- अपने क्षेत्र में कौन-से फल (जैसे: आम, अमरुद, लीची, कीवी) अच्छी तरह उगते हैं; उनको पहचानें और देखें कि वहां प्रसंस्करण-उपकरण उपलब्ध हैं या नहीं।
- स्थानीय किसान उत्पादक संगठन (FPO) या सहकारिता

गठित करें — मिलकर निवेश करें।

- ठंडा भंडारण व परिवहन की सुविधा देखें — स्थानीय कृषि विभाग से संपर्क करें।
- पैकिंग व ब्रांडिंग पर ध्यान दें
 "जबलपुर फ़ूट्स", "मध्य-प्रदेश ऑर्गेनिक्स" जैसे नाम हो सकते हैं।
- तैयार उत्पादों (जूस, ड्राय फलों, फ्रोजन कट-फल) का बाजार तलाशें — ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी आज उपलब्ध हैं।
- सरकार द्वारा उपलब्ध योजनाओं व अनुदानों की जानकारी रखें एवं आवेदन करें।
- संयोजन करें खेत से प्रसंस्करण तक एक शृंखला बनाएं। इससे उत्पादन-से- बिक्री तक की दूरी कम होगी।
 स्व-निर्मित प्रसंस्करण

इकाइयों में छोटे स्तर से

शुरुआत करें — अनुभव बढ़ने पर स्केल-अप करें।

८. निष्कर्ष

संक्षिप्त में — यदि किसान सिर्फ फल उगाकर बेचते रहे. तो उन्हें सीमित आय ही होगी। लेकिन यदि वे प्रसंस्करण व मूल्य-संवर्धन की दिशा में कदम उठाएँ — बेहतर गणवत्ता, कम लॉस, तैयार उत्पाद, मार्केटिंग, बेहतर सरकारी सहायता — तो उनकी आय दोगनी या उससे भी अधिक हो सकती है। यह न केवल उनकी आर्थिक स्थिति सुधारेगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सशक्त करेगा। आज का समय इस दिशा में बहुत अनुकूल है — उपभोक्ता बदल रहे हैं, स्वास्थ्य-प्रवणता बढ़ रही है, सरकार के अनुदान उपलब्ध हैं। यदि सही दिशा में योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाए — तो फल-प्रसंस्करण किसानों के लिए एक सनहरा अवसर है।